International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-6 Nov-Dec-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

उत्तर प्रदेश के विकास में जनपद आज़मगढ़ के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की भूमिका

श्री चन्द्र राजभर*

एम०ए०(नेट) भूगोल-शोध छात्र,आर०आर०पी०जी० कॉलेज, अमेठी, उ०प्र०

डॉ० अर्जुन प्रसाद पाण्डेय**

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग, आर०आर०पी०जी० कॉलेज, अमेठी, उ०प्र०

संक्षेपण

इस कार्य में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रिया पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में ग्राम विकास की कठिनाइयों की जाँच की जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के साथ संघर्ष करना जारी रखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इन स्थानों में, डॉ हेमलता अवल व्यापक दृष्टिकोण के लिए तर्क देना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व बैंक जैसे संगठनों के मॉडल से प्रेरित है। यह दृष्टिकोण कृषि इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करती हैं कि विकास के लिए पर्याप्त मौलिक उपयोगिताएं नहीं हैं। इस पत्र का उद्देश्य गांव के उत्थान के लिए एक प्रणालियों में सुधार और आय उत्पादन के अवसरों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित है। विशेष रूप से, यह ग्रामीण जीवन की पेचीदगियों की पूरी समझ रखने के लिए सामाजिक विशेषताओं और आर्थिक चर के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। खेती, पशुपालन, ग्रामीण हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग कुछ प्रमुख गतिविधियाँ हैं जिन्हें गांवों की आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक होने के रूप में उजागर किया गया है। इसके अलावा, लेख गांवों के विकास पर एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो समाज, राजनीति और संस्कृति की उन्नति को ध्यान में रखता है। राज्य-नियोजित आर्थिक मॉडल को लागू करने के लिए पूरे इतिहास में कई असफल प्रयास किए गए हैं। नतीजतन, किसानों और राजनेताओं ने ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता को दूर करने के लिए मिलकर काम किया है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण शामिल है। इस तथ्य के बावजूद कि लेख महानगरीय क्षेत्रों में गरीबी की व्यापकता को स्वीकार करता है, यह गरीबी को कम करने के एकमात्र प्रयास के लिए ग्राम विकास परियोजनाओं को सीमित करने के खिलाफ वकालत करता है। कृषि में व्यावसायीकरण के कई स्तरों, साथ ही भूमि संबंधों और धन असमानता पर इसके प्रभावों पर इस लेख में चर्चा की गई है। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करता है, कृषि उत्पादों के उचित वितरण का आश्वासन देता है, और गरीबी और निरक्षरता के मुद्दों से निपटता है। इस रणनीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदायों में बदलना है, जो भारत के औद्योगिकीकरण ने जो विशिष्ट मार्ग अपनाया है, जो पश्चिम के समाजों के अनुभव से अलग है।

प्रमुख शब्द

ग्रामीण विकास, कृषि अर्थशास्त्र, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, गांव की आत्मनिर्भरता, गरीबी निवारण रणनीतियाँ, भारत की ग्रामीण-शहरी गतिशीलता

परिचय

भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है और आज भी सत्तर प्रतिशत लोग कृषि उपज पर निर्भर हैं। इसलिए, गाँव के विकास की किसी भी पहल में कृषि प्रणाली में सुधार के प्रयास शामिल होने चाहिए। भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन से ऊपर उठाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसा कि डॉ. हेमलता अवल ने कहा है। ग्राम उत्थान के कुछ विशेषज्ञ इसे एक मूल्यवान सबक मानते हैं और विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संगठनों से प्रेरणा लेते हुए योजना बनाते समय आय के अवसरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का तर्क देते हैं। गाँवों का विकास और सुधार अर्थशास्त्र और सामाजिक संरचना दोनों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। गांवों की अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन को समाजशास्त्र से अलग करना आवश्यक है। खेती, पशुपालन, ग्रामीण हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग जैसी अन्य गतिविधियों के साथ-साथ पेड़ों को अक्सर ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालाँकि, एक और दृष्टिकोण है जो गाँव के विकास को समाज, राजनीति और संस्कृति सहित गाँव के जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यापक प्रगति के रूप में देखता है।[1] इस व्यापक दृष्टिकोण को परिभाषित करना अधिक कठिन है और इसमें कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अतीत में, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राज्य-योजनाबद्ध मॉडल लागू करने के प्रयास विफल रहे। इसके बजाय, ग्रामीण गरीबी से निपटने के लिए किसान और राजनेता एकजुट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर स्तर तक महाविद्यालयों की स्थापना करके गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया गया है। गाँवों का उत्थान आवश्यक है क्योंकि गरीबी इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है। हालाँकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि गरीबी शहरों में भी मौजूद है, हालाँकि अक्सर बड़ी कॉलोनियों के पीछे छिपी होती है। इस प्रकार, गाँव के विकास का ध्यान केवल गरीबी तक सीमित रखना अनुचित होगा।[2] विभिन्न फसलों के लिए व्यावसायीकरण का पैमाना भिन्न-भिन्न था। उदाहरण के लिए, कम आबादी वाले क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए सीमित बागान क्षेत्रों की आवश्यकता होती थी और यह गुलामी के एक रूप के समान, अनुबंध के तहत दूरदराज के क्षेत्रों से भर्ती किए गए श्रमिकों पर निर्भर था। उन्नीसवीं सदी में शहरों और गांवों दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के बावजूद, किसानों को अक्सर उनकी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता था, और व्यावसायीकरण के परिणाम भूमि संबंधों के निर्माण में स्पष्ट थे। राजस्व और कराधान से संबंधित तुर्की नीतियों के साथ-साथ देशी राजाओं और जमींदारों द्वारा गांवों के शोषण ने रैयतों, किरायेदार किसानों के बीच धन असमानता और छोटे साहूकारों और दुकानदारों की अनुपस्थिति को और बढ़ा दिया। यदि भारत को औद्योगीकरण के उस रास्ते पर चलना है

[1] डॉ. हेमलता : भारत को व्यवस्था, युगोत्तर प्रकाशन, शाहदरा, सं. 2013..
[2] सरकार सुमत: आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नयी, 2018.

जिसने पश्चिम में ग्रामीण समाजों को बदल दिया, तो स्वदेशी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और उपज के अधिक न्यायसंगत वितरण पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में अनुभव किया जा रहा औद्योगीकरण पश्चिम से भिन्न है। अर्थशास्त्रियों के बीच अलग-अलग विचारों के बावजूद, कृषि के व्यावसायीकरण, अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के उत्पादन और ग्रामीण समृद्धि के बीच एक संबंध है। इस प्रवृत्ति के कारण किसानों के बीच भेदभाव पैदा हुआ है, जिससे अंततः उत्पादकता में वृद्धि हुई है; हालाँकि, यह उत्पादकता गाँव के विकास में किस हद तक योगदान देती है, यह एक प्रश्न बना हुआ है। संक्षेप में, गाँवों का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक शामिल होते हैं। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो भारत में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करे। स्वदेशी संसाधनों को अधिकतम करने, उपज का उचित वितरण सुनिश्चित करने और गरीबी और अशिक्षा से निपटने पर ध्यान केंद्रित करके, गांवों का उत्थान किया जा सकता है और उन्हें समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदायों में बदला जा सकता है।[3]

ग्रामीण विकास: अर्थ एवं प्रकार

ग्रामीण विकास की अवधारणा किसी एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे देश का परिदृश्य विविध एवं विविधतापूर्ण है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, जो पंजाब से बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ है। गांवों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी का दृष्टिकोण ग्राम पंचायत प्रणाली पर केंद्रित था। डॉ. उमेश साद दत्त ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उच्च स्तर पर प्रकाश डालते हैं, जहां कृषि काफी हद तक प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है और सरकार से सीमित सहायता प्राप्त करती है। रवि नाथ टैगोर का "नकेतन प्रोजेक्ट," एफ.आई. गुनगांव परियोजना, और महात्मा गांधी की सेवा ग्राम परियोजना ग्रामीण विकास के प्रयासों का उदाहरण है। नेहरू ने ब्लॉक मॉडल दृष्टिकोण पर जोर दिया, लेकिन यह पूरे ग्रामीण समुदाय को शामिल करने में विफल रहा। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, जो केवल गरीबी उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नतीजतन, गरीबी उन्मूलन उपायों पर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। विशेष रोजगार के अवसर प्रदान करना, बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सहायता, भूमि सुधार, घरों का निर्माण और पानी तक पहुंच प्रदान करना और स्वच्छता सुविधाएं गांवों के उत्थान के लिए कुछ रणनीतियां हैं। डॉ. उमेश साद दत्त कहते हैं कि ग्रामीण विकास की अवधारणा का एक लंबा इतिहास है। यह गणतंत्र के दौरान अस्तित्व में था और मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। डॉ. उमेश कुमार दत्त बताते हैं कि इंग्लैंड का लक्ष्य अपनी औद्योगिक जरूरतों को

[3] पांडेय एच. एल. : गांधी, नेहरू, टैगोर एवं अम्बेडकर, सुमत प्रकाशन, इलाहाबाद, स. 2001.

पूरा करने के लिए भारत के कृषि संसाधनों को विकसित करना था। हालाँकि, भारत के कच्चे माल की गुणवत्ता ने एक चुनौती पेश की। इसे संबोधित करने के लिए, 1833 के चार्टर अधिनियम ने यूरोपीय लोगों को भारत में बसने और संपत्ति हासिल करने की अनुमति दी, जिससे चाय, कॉफी, नील और जूट बागानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश हुआ। कृषि पर अत्यधिक दबाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकृत कर दिया, जिससे खेती कठिन हो गई।[4] उत्पादन के बजाय कृषि पर निर्भर बढ़ती जनसंख्या ने गरीबी में वृद्धि में योगदान दिया। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों ने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में बाधा डाली, जिससे किसान गरीबी में फंस गए। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में स्थिर कृषि उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि ने गरीबी को और बढ़ा दिया। गांवों के उत्थान के लिए कृषि के व्यावसायीकरण की जांच करना महत्वपूर्ण है। पहले, कृषि केवल आजीविका का साधन थी, व्यवसाय का विकल्प नहीं। हालाँकि, कपास, जूट, मूंगफली, तिलहन, गन्ना और तंबाकू जैसी फसलें तेजी से लाभदायक हो गईं। इसके अतिरिक्त, मसालों, सब्जियों और फलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से चाय और रबर के मामले में स्पष्ट थी, जहां मीडिया कवरेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्रामीण विकास नीतियां एवं उपलब्धियां

गांवों के उत्थान के लिए प्रभावी रणनीतियों के कार्यान्वयन के बिना ग्रामीण विकास की उपलब्धियों की पूरी सराहना नहीं की जा सकती। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों की अंतर्निहित विचारधाराओं और उद्देश्यों की जांच करना महत्वपूर्ण है। डॉ. देवे शर्मा के अनुसार, ग्रामीण विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन, भूमि उपयोग, प्रौद्योगिकी, कृषि, रोजगार, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। ये गतिविधियाँ मुख्य रूप से कृषि और शिल्प के इर्द-गिर्द घूमती हैं, वास्तुकला अक्सर कृषि विकास में सहायक भूमिका निभाती है। भूमि-संबंधी नीतियों का महत्व कृषि से परे तक फैला हुआ है और ग्रामीण विकास की गति में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। भूमि स्वामित्व पर आधारित ग्रामीण जीवन की खुशी और खुशहाली, ग्राम प्रगति पहलों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में काम करती है।[5] हालाँकि, भूमि के अत्यधिक दोहन के कारण बढ़ती बेरोज़गारी और घटती उत्पादकता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक अस्थायी रूप से भूमि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, एक मजबूत खाद प्रणाली की अनुपस्थिति या गाय के गोबर जैसे प्राकृतिक उर्वरकों की कमी गांवों के उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई रणनीतियों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा,

[4] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1897 के अंधवेशन:- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गतिविधियां, डॉ. गोपाल, अभिनभ प्रकाशन, मेरठ, सं. 1998.
[5] डॉ. उमेश कु मार : ग्रामीण विकाश की अवधारणा, पालवी प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2014.

ग्रामीण विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों को लागू करते समय, उन प्रौद्योगिकियों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो अत्यधिक श्रम कटौती के बिना लाभ को बढ़ावा देते हैं। ध्यान न केवल उत्पादकता बढ़ाने पर बल्कि ग्रामीण समुदायों के भीतर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी होना चाहिए। हालाँकि कृषि योजनाएँ गाँवों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन ये अंतिम समाधान नहीं हैं। जीवन स्तर को बनाने और ऊंचा उठाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से परे रणनीतियों और गतिविधियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, यह एकीकरण वर्तमान में नहीं हो रहा है। ग्रामीण उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाते समय, ग्रामीण संसाधनों की नींव और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। डॉ. देवे शर्मा बताते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है और नीति निर्माताओं द्वारा रोजगार बढ़ाने के दावे अक्सर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सूखे और बाढ़ जैसी मौसम संबंधी विफलताओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, जिससे आय में उतार-चढ़ाव हो सकता है।[6] इसके अलावा, कृषि में रोजगार मौसमी होता है, जिससे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से साल भर रोजगार प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भीतर गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। हालाँकि, भूमि के असमान वितरण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, जिसमें कई किसानों के पास केवल छोटे भूखंड होते हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आय-अर्जन क्षमता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सभी ग्रामीण भूमि उत्पादक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना भी था। भूमि सुधार ग्रामीण समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कृषि उत्पादकता के लिए उन्हें प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।[7] दिलचस्प बात यह है कि छोटे खेतों में बड़े खेतों की तुलना में अधिक उत्पादकता होती है, क्योंकि छोटे पैमाने के किसान अपने खेतों में अधिक प्रयास करते हैं। इसलिए, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियां कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

भारत में ग्रामीण विकास का अध्ययन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक कारकों के अंतर्संबंधों पर आधारित है। इस शोध ने उजागर किया है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और स्वावलंबन की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय सृजन के अवसरों का विस्तार और उन्हें सशक्त बनाना प्रमुख रहा है। इसके साथ ही, गरीबी और

[6] बी. एल. : आधुनिक भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, सं. 2003.
[7] डॉ. संद8प : ग्रामीण विकाश की योजनाओं की उपलब्धियां, पल्लवी प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2014.

अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष में शिक्षा की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को केवल आर्थिक विकास तक सीमित न रखते हुए, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समान महत्व देना होगा। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग, कृषि उपज का न्यायपूर्ण वितरण, और गरीबी तथा अशिक्षा के खिलाफ प्रयास शामिल हों। अंततः, इस शोध का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाजों को समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदायों में बदलने की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करना है।